PARIPREKṢYA, Vol. XXVI, Year 2017, ISSN 2278-0602

60

भारत–नेपाल आर्थिक संबंध : समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में

डॉ० आभा सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान, विभाग, कु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविधालय, बादलपुर गौतमबुद्ध नगर

भारत की नेपाल के साथ कई वास्तविक समस्याएँ है। भारत की सबसे प्रमुख शिकायत यह है कि भारत के साथ खुली सीमा से उत्पन्न भारत की वास्तविक सुरक्षा चिंताओं के लिए नेपाल ने पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई हैं। ये समस्याएँ कई दशकों से भारत के लिए सतत सिरदर्द बनी हुई हैं और 1999 में काठमांडु से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान के आरक्षण ने इस असंवेदनशीलता को नाटकीय ढंग से चित्रित किया। नेपाल विदेशी शक्तियों और गैर राज्य तत्त्वों द्वारा खुफिया और विध्वंसक कार्रवाइयों के लिए एक उपयोगी और महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया हैं खुली सीमा घुसपैठ करने के लिए जासूसों का आना जाना, जाली नोटों के व्यापार, हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी, कट्टरपंथी धार्मिक समूहों और गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों के संचालन को आसान बना देती है। चीन सहित नेपाल में विदेशी शक्तियों की उपस्थिति और गतिविधियाँ उनकी भारत संबंधी नीति से अनन्य रूप से जुड़ी हुई है।

पिछले छह [illegible] में अन्य कारकों.के अतिरिक्त नेपाल तिब्बत के साथ अपनी भौगोलिक स[illegible] का फायदा उठाकर, बखूबी अपने लिए भारत के बनाम बड़ी राजनैति[illegible] बनाने में सफल रहा है। नेपाल में भारत की महती उपस्थिति और प्रभाव अब वैसा नहीं रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था। एक अभूतपूर्व कदम के रूप में प्रधानमंत्री प्रचंड ओलंपिक खेलों के समारोह में भाग लेने के बहाने अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन गये। यद्यपि नेपाल महत्त्वपूर्ण रूप से भारत पर निर्भर है, उसने अपने विदेशी संबंधों और संपर्कों में विविधकरण किया है। भारत ने, कभी मौन रूप से, और कभी अनिच्छा से, 1950 की संधि की विषय–वस्तु और भावना दोनों में नेपाल के कई विचन स्वीकार किये हैं और उत्तरोत्तर नेपाल को व्यापार और पारगमन के मामलों में काफी उदारता दिखाई है। समय–समय पर, नेपाल 1950 की संधि में संशोधन की माँग करता रहा है। हाँलांकि भारत ने कई बार सार्वजनिक रूप से संधि संशोधन के प्रति सम्मति प्रकट की है, लेकिन नेपाल ने इस बारे में तत्परता नहीं दिखाई है। यहाँ तक कि माओवादी भी जो भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा को बंद करने, 1950 की संधि को समाप्त करने और भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती रोकने संबंधी आवाज उठाते रहते हैं, चुनाव के बाद वे